>

Title: Further discussion on resolution regarding special economic development package for the desert regions of the country (Discussion concluded and Resolutions negatived).

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House would now take up Private Members Bills and Resolutions. हम माननीय सदस्यों को सूचित करते हैं कि इस संकल्प पर 2 घंटे 57 मिनट का समय पहले लिया जा चुका है। इस प्रकार इस पर चर्चा के लिए आबंटित समय अब समाप्त हो गया है। चूंकि संकल्प पर चर्चा में भाग लेने के लिए अभी एक माननीय सदस्य और शेष हैं, इसलिए सदन को संकल्प पर आगे चर्चा के लिए समय बढ़ाना पड़ेगा। यदि यह सभा सहमत हो तो संकल्प पर चर्चा के लिए समय को इसके निपटान के लिए आगे बढ़ा दिया जाए।

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे यहां से बोलने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, बोलिये।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): आदरणीय उपाध्यक्ष जी, हमारे माननीय सांसद श्री हरीश चौधरी जी द्वारा 26 अगस्त, 2011 को जो संकल्प पेश किया गया है, देश के मरु प्रदेशों के लिए विशेष आर्थिक विकास पैकेज की जो इन्होंने मांग की है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मेरा संसदीय क्षेत्र साबरकांठा भी राजस्थान से जुड़ा हुआ है। आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक रूप से हम वीर भूमि राजस्थान से जुड़े हुए हैं। होली हमारे यहां दोनों का एक बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। मेरा क्षेत्र साबरकांठा एक आदिवासी, दलित एवं पिछड़े लोगों का बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सारा हमारे यहां जो क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र कृषि एवं पशुपालन आधारित जीवन-यापन करता है। अरावली गिरिमाला की शुरूआत हमारे क्षेत्र से ही होती है और इसके कारण ज्यादातर जमीन कंकरीली और पथरीली होने के कारण बिन उपजाऊ है। अगर सिंचाई की बात करें तो पूरे क्षेत्र में सिंचाई की पूरी सुविधा नहीं है, जिसके कारण कृषि का विकास जितना होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ है। आज भी सिर्फ मानसून सीजन पर आधारित वहां की कृषि है, बाद में किसान वहां खेती नहीं कर सकते।

रेलवे का भी पर्याप्त विकास नहीं होने के कारण क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। आज हमारे क्षेत्र में एक भी रैक पाइंट नहीं है। वहां किसान पीड़ित हैं, दुखी हैं, उससे कृषि भी प्रभावित होती है। हमारे क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए, वह नहीं हुआ है। रेलवे का विकास नहीं होने के कारण आज हमारे क्षेत्र में उद्योगों का भी विकास नहीं हुआ है। इसी के कारण हम आज भी पीछे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अपने क्षेत्र साबरकांठा के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग करता हूं, ताकि मेरे पिछड़े हुए संसदीय क्षेत्र साबरकांठा का सर्वांगीण विकास हो सके।

श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली): महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। श्री हरीश चौधरी जी ने 26 अगस्त, 2011 को जो संकल्प पेश किया गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं और मैं उसका समर्थन भी करता हूं। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की थोड़ी सी बात रखना चाहता हूं।

महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सभी माननीय सांसदों ने अपने-अपने राज्यों की, अपने-अपने क्षेत्र की बात रखी। आज हमारा देश बहुत बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहा है। हमारे क्षेत्र में, मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूं, गुजरात के अमरेली से, अमरेली जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है। वहां कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। वह किसान, मजदूर आधारित क्षेत्र है। वहां और कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि आज हमारे देश में संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन इनका सदुपयोग कैसे किया जाये, यह सही तरीके से आज तक नहीं हुआ है। सरकार को भी यह पता होना चाहिए कि इनका सदुपयोग कैसे किया जाये? इस देश का विकास जितना भी अच्छा होगा, उतना सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जो पिछड़ा जिला है, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जो पिछड़े लोग हैं, उन्हें मूल स्वरूप में लाना है तो सरकार को उस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।

महोदय, हमारे देश का विकास, हमारे देश के योजना आयोग के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि हमारे देश के योजना आयोग में जो लोग बैठे हैं, उन्हें पता नहीं है कि वास्तविक स्थिति क्या है? अगर उन्हें इसके बारे में पता होता तो आज देश में यह स्थिति नहीं होती।

महोदय, यदि मैं गुजरात की बात करूं तो जो गुजरात राज्य है, वह सरकार की कृपा से विकास के मामले गुजरात आज नम्बर एक पर है। यदि केंद्र सरकार गुजरात के विकास में कोई बाधा न डाले और नःस्वार्थ उसे मदद करे तो मैं यह वादा करता हूं कि आज गुजरात पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं, वरन् पूरे विश्व में वह नम्बर एक

का स्थान लेगा, आज गुजरात इतना विकास कर रहा है। एक दिन ऐसा आयेगा कि गुजरात अमेरिकन राज्यों को पीछे छोड़ देगा। पूरे गुजरात के लोग ऐसा दिन देखने के लिए बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार बार-बार उसके विकास में रोड़ा डाल रही है। गुजरात में निम्नलिखित जो योजना का प्रश्न है, तीन-तीन साल से हम यहां आये हैं, लेकिन अभी तक एक प्रश्न का भी हल नहीं हुआ है। विकास तभी होता है जब क्षेत्र में पूरी सुविधा हो। अगर आज मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो मुझे यहां दिल्ली आने के लिए अपने क्षेत्र से 300 किलोमीटर दूर अहमदाबाद आना पड़ता है क्योंकि मेरे क्षेत्र में रेलवे की सुविधा नहीं है। आज हम संसद के 60 साल मना रहे हैं। आज आजादी को 60 साल से ज्यादा हो गये हैं, लेकिन रेलवे की वहां कोई सुविधा नहीं है। वहां मेरे क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल भी नहीं है। वहां सेंट्रल स्कूल भी नहीं है तो वहां के गरीब बच्चे कहां पढ़ेंगे? यह भी एक सोचने की बात है। सबसे पहले किसी समाज का, किसी देश का, किसी राज्य का अगर विकास करना है तो सबसे पहले शिक्षा अनिवार्य हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कह रहा हूं कि मेरा जो प्रश्न है, मेरे क्षेत्र के जो काम बाकी हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार) : महोदय, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं जिस भावना से, जिस भाव से और जिस उद्देश्य से यह रिजोल्यूशन सदन में लाया गया है, उस पर चर्चा हुई है, मैं उसका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं और उस भावना के साथ अपने आपको जोड़ता हूं। यह बिल्कुल सही बात है और नःसंदेह सारा सदन ही इस बात को स्वीकार करेगा कि हमारे विशाल मुल्क के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो आज तक पूरी तरह से विकसित नहीं हो सके हैं। क्षेत्रीय विषमताएं हैं। क्षेत्रों, जिलों और राज्यों में डेवलपमेंट का बहुत फर्क है उनके खास कारण हैं। ये प्रस्ताव जो रेतीले क्षेत्रों के बारे में रखा गया है जहां पर विकास की गति उतनी जोर नहीं पकड़ पाई जितनी उसको पकड़नी चाहिए थी उसके बहुत कारण हैं जिसके बारे में सभी सम्माननीय सदस्यों को पता है। इस पर चर्चा भी की गई है। बहुत से सम्मानीय साथी जिन्होंने इस पर चर्चा की - हरीश चौधरी साहब, हुक्मदेव नारायण यादव जी, शैलेन्द्र कुमार जी, सतपाल महाराज जी, भतृहरि महताब जी, सेम्मलई जी, चौधरी लाल सिंह जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, अधिरंजन जी और अन्य सदस्यों ने बहुत योगदान इस चर्चा में दिया है। उन्होंने जो-जो कहा है मैं उसके बारे में बात करूंगा। उसके पहले मैं कुछ तथ्य, कुछ आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूं।

इस प्रस्ताव के माध्यम से विशेष आर्थिक पैकेज की डिमांड की गई है। उसका लक्ष्य बहुत उचित है और सराहनीय है। यकीनी तौर पर बहुत बड़ा रेतीला क्षेत्र इस देश में है। इसमें हमारे सात राज्य, चालीस जिले और दो सौ पैंतीस ब्लाक्स हैं। इनका कुल क्षेत्र मिला कर चार लाख सतावन हजार नौ सौ उनचास स्कवायर मीटर बनता है। बहुत बड़ा इलाका है जो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है। इसके लिए साधनों की आवश्यकता है और साधन मुहैया भी कराए गए हैं।

मैं कुछ आंकड़े संक्षिप्त रूप मे पढ़ना चाहूंगा। वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2012 तक विभिन्न परियोजनाओं के तहत हमने 64438 करोड़ रूपये इन क्षेत्रों के विकास में लगाए हैं। मनरेगा के तहत 47879 करोड़ रूपये, इदिरा आवास योजना के तहत 8909.45 करोड़ रूपये, बीआरजीएफ के तहत 4393.50 लाख रूपये, बीएडीपी के तहत 1211.87 करोड़ रूपये, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1279 करोड़ रूपये और आईडब्ल्यूएमपी (इंटिग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम) के तहत करीब 1727 करोड़ रूपये हमने खर्च किए हैं जो कि कुल मिला कर 64438 करोड़ रूपये बनते हैं।

जब से स्कीम शुरू हुई थी, अगर वर्ष 1996-97 से लें तो हमने 75420.52 करोड़ रूपये इन इलाकों पर खर्च किए हैं। उसका फायदा भी हुआ है। इसका मूल उद्देश्य था कि रेतीले इलाकों की प्रोडक्टिविटी बढ़े और जो सॉइल इरोजन हो रहा है वह कम हो, पानी का जो मसला है वह ठीक हो, कनेक्टिविटी हो, कुछ उद्योग लगें, जैसा कि बताया गया कि पशुपालन, डेयरी डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर की परियोजनाएं चलें। विभिन्न प्रान्तों की तरह इन सूबों का पूरा विकास हो सके। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम पूरी तरह से अपने लक्ष्य में कामायाब हुए हैं। मेरा यह दावा कभी नहीं है कि हम पूरी तरह कामयाब हुए हैं। सफर लंबा है। हमें बहुत कुछ आगे करना है और हमारी सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है कि इन क्षेत्रों की ओर पूरा ध्यान दिया जाए। जिस भावना के साथ ध्यान देना चाहिए उस भावना के साथ हम इन मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं।

15.45 hrs.

(Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

सभापति जी, मैं राजस्थान के मुतालिक कुछ कहना चाहता हूं। इन इलाकों में सब से बड़ा रेतीला इलाका राजस्थान है। एक लाख पचानवे हजार किलोमीटर से ज्यादा रेती का एरिया राजस्थान में है। इसमें हमने खास तौर पर मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, बैकवर्ड रिजन ग्रांट फंड, बार्डर एरिया डैवलपमैंट प्रोग्राम, डैजर्ट डैवलपमैंट प्रोग्राम और इंडीग्रेटेड वाटरशैड मैनेजमैंट प्रोग्राम के तहत तवज्जह दी है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि केवल राजस्थान में पिछले पांच सालों में इन विभिन्न परियोजनाओं के तहत हमने 22 हजार 61 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। चूंकि चुनौती इतनी बड़ी है, मसला इतना गंभीर और व्यापक है कि कुछ भी कर लें, ऐसा लगता है कि समुद्र में एक बूंद है। मगर लक्ष्य सामने है, इरादा नेक है, नीयत में कोई फर्क नहीं है और मिलकर इन क्षेत्रों को विकसित करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने हमेशा यह कहा है कि जहां तक विकास का मसला है, जहां तक डैवलपमैंट का सवाल है, इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां तक विकास का सवाल है, खास तौर से जहां तक इस तरह के पिछड़े इलाकों के विकास का सवाल है, हमें अपनी राजनीति को एक रचनात्मक पहलू में ढालना चाहिए।

मैं सदन के समक्ष एक बात और रखना चाहूंगा।...(व्यवधान) मध्य प्रदेश भी बीच में ही है। मैंने कहा कि हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, कुछ ब्लॉक आंध्र, हरियाणा और गुजरात के, ये रेतिले एरियाज का सवाल है, इसमें मध्य प्रदेश नहीं आता। मैं जिक्र कर रहा था कि जहां तक डैजर्ट डैवलपमैंट प्रोग्राम का सवाल है, इसके तहत मैंने जो प्रोग्राम बताए, वे बताए ही, मगर हमने कुछ खास प्रोजैक्ट्स चलाए हैं। मसलन हमने राजस्थान में इन प्रोग्राम्स के तहत 6,581 प्रोजैक्ट लिए हैं। उनकी टोटल प्रोजैक्ट कॉस्ट 2187.20 करोड़ रुपये है जिसमें से 1515 करोड़ रुपये हमने रिलीज़ कर दिए हैं। इसका असर देखने को मिल रहा है। 37.79 लाख हैक्टेयर भूमि पर इसका असर पड़ा है। जहां तक मेरे आंकड़े हैं, मुझे जो रिपोर्ट दी गई है, उससे स्पष्ट हुआ है कि जो इसके मुख्य उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों की पूर्ति और प्राप्ति में हमें कुछ सफलता जरूर मिली है। मसलन जो इकोलॉजिकल बैलैंस की बात थी, पानी, लाइव स्टॉक और ह्यूमन रिसोर्सेज़, इन्हें एक सांचे में ढालने और बांधने का जो उद्देश्य था, उसमें हम किसी हद तक कामयाब हो सके हैं। मगर जैसे मैंने कहा कि सफर लम्बा है, मिलकर दूरी पूरी करनी है। मैंने अभी जो आंकड़े गिए, वे 6 हजार कुछ के थे जो पिछले सालों में राजस्थान के लिए किए गए, लेकिन अगर भारतवर्ष का नक्शा लेकर चलें, हमने 15,746 प्रोजैक्ट्स के तहत 7.87 मिलियन हैक्टेयर के विकास के लिए धनराशि मुहैया कराई है और इसमें हमें कुछ न कुछ सफलता जरूर प्राप्त हुई है।

अंत में एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। हमारे मैम्बरान्स ने यहां जो स्पैसीफिक सुझाव रखे हैं, मैं उनका जिक्र संक्षेप में करना चाहूंगा। अर्जुन राम मेघवाल जी ने इनकम टैक्स ऐग्ज़ैम्शन की बात की, बार्डर एरिया डैवलपमैंट को और साक्षर, कारगर करने की बात की। आपने फैमिन कोड के बारे में जिक्र किया। ये सभी सुझाव

सैद्धान्तिक तौर पर काफी अहम हैं। हम इन्हें जरूर ध्यान में रखेंगे और देखेंगे कि इन पर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सतपाल महाराज साहब ने सोलर एनर्जी, इलैक्ट्रिफिकेशन और विंड टरबाइन्स की बात की। यह बहुत अहम सुझाव है। इसके लिए रिन्युएबल एनर्जी प्रोसैस के अंदर पूरा एक प्रोग्राम चल रहा है। चेयरमैन साहब, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही कारगर सुझाव है। मेरी खुद की यह इच्छा होगी और मैं जो कर पाऊंगा करूंगा, कि खास तौर पर सोलर एनर्जी, इलैक्ट्रिफिकेशन मिशन, विंड टरबाइन्स को इन एरियाज में डाला जाए जिससे एक व्यापक सुधार आए और विकास हो। भर्तृहरि महताब जी मेरे दोस्त हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा कि ऑयल एंड गैस की शिक्षा में स्टूडैंट्स को स्पैशल ग्रैजुएशन सैर्टिफिकेट्स मिलें क्योंकि राजस्थान में ऑयल एंड गैस मिला है। इन एरियाज में ऑयल एंड गैस होगा, लोग प्रोत्साहित होंगे कि टैक्नीकल एजुकेशन मिले ताकि उन्हें स्पैशल सैर्टिफिकेट मिलें। बहुत कारगर और रचनात्मक सुझाव आए। इन पर जरूर ध्यान दिया जाएगा। हुक्मदेव साहब ने अपने भाषण में बहुत चर्चा की और कहा कि गरीब के लिए संवेदना नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। वे हमारे सम्माननीय और सीनियर नेता हैं। हमारे मैम्बर हैं। मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हूं और यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो दर्शन था, कांग्रेस पार्टी का भी वही दर्शन है। देश के लिए सारे सदस्यों का वही दर्शन है, सारे भारतवर्ष का वही दर्शन है। उस दर्शन से हम न पीछे चूके हैं, न आज चूक रहे हैं और न आगे चूकेंगे।

सभापति महोदय, आखिर में मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। जहां तक विकास का सवाल है, यह एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर सारा सदन एकजुट होकर काम करे। इसमें कोई दलगत राजनीति की बात नहीं है। मैं कोई प्वाइंट स्कोर नहीं कर रहा हूं, अपने आपको थपथपा नहीं रहा हूं। किसी को दोष नहीं दे रहा हूं और यह भी नहीं कह रहा हूं कि जो कुछ हमें करना चाहिए, वह हम पूरी तरह से कर पाये हैं। जैसा मैंने कहा कि सफर लंबा है, रचनात्मक राजनीति हो और एक शेर, विजय बहादुर जी उसे जानते हैं, वह बहुत अच्छा शेर है। उसे मैं आज पढ़कर अपनी बात खत्म करूंगा--

नेक हुक्मरान बहुत जल्द वह वक्त आयेगा,

जब हमें जीस्त के अदबार परखने होंगे,

अपनी जिल्लत की कसम, आपकी इज्जत की कसम,

हमें ताज़ीम के मयार बदलने होंगे।

सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ किया है, जो आंकड़े मैंने रखे हैं, उनको समकक्ष रखते हुए और अपनी भावनाओं को आपकी भावना के साथ जोड़ते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आप अपना रेजोल्यूशन वापस ले लें। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Now, Shri Harish Chaudhary to reply. He is not present.

Hon. Members, as Shri Harish Chaudhary, who is the mover of this Resolution, is not present in the House to exercise his right of reply, the Resolution moved by Shri Harish Chaudhary has to be put to the vote of the House.

The question is:

> "This House expresses its deep concern over the backwardness prevailing in the desert regions of the Country and urges upon the Government to prepare and implement a special economic package for:--
>
> (i) overall development of desert regions on the lines of the economic package provided to the north-eastern States to mitigate the problems being faced by the people living in desert regions; and
>
> (ii) enabling the people of these regions to achieve a level of socio-economic development at par with the people living in other parts of the country."

The Resolution was negatived.